Priority Industry Status to Oodubathi Industry

2230. SHRI K. MALLANNA: Will the Minister of INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether any demand has been made by the Mysore Oodubathi Manufacturers Association that Centre should change its criterion of 20 per cent exports for recognition as priority industry and sanction priority industry status to the Oodubathi industry soon; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES (SHRI B. P. MAURYA): (a) No, Sir. There is no record of any such representation being received by Government .

(b) Question does not arise.

हरिजनों पर अत्याचारों में वृद्धि

2231. **श्री जांबुवन्त धोते:**
श्री रामावतार शास्त्री :
श्रीमती रोजा देशपांडे :
डा० रानेन सेन :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में हरिजनों को संरक्षण देने के बजाये, उन पर अत्याचारों और उनके प्रति अमानवीय व्यवहार की घटनायें बढ़ रही हैं और गत दो वर्षों में ऐसी घटनाओं की संख्या बहुत अधिक रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) गत दो वर्षों में, राज्यवार, ऐसी कितनी घटनायें घटी और उनमें कितने व्यक्ति मारे गये ; और

(घ) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये क्या विशेष कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही हैं और सदन के पटल पर रख दी जायेंगी ।

(घ) राज्य सरकारें ऐसे मामलों में कानून के अन्तर्गत उपयुक्त निरोधात्मक तथा दण्डात्मक कार्यवाही भी करती हैं । केन्द्रीय सरकार समय समय पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियो के सदस्यों पर किए गए अपराध के मामलों में कुशल जांच तथा मुकदमा चलाने की आवश्यकता पर राज्य सरकारों पर जोर डालती रही हैं । 1974-75 में हुई क्षेत्रीय परिषदो की बैठकों में गृह मन्त्री ने इस समस्या की ओर मुख्य मंत्रियों का ध्यान आकर्षित किया था तथा अनुसूचित जातियो तथा अनुसूचित जन जातियों के सदस्यों पर अपराधो की शिकायतों की शीघ्र जांच के लिए राज्य और जिला स्तरों पर विशेष प्रबन्ध करने की आवश्यकता पर बल दिया था । अनुसूचित जातियों/जनजातियो की शिकायतों पर विचार करने अथवा सरकारी सेवाओं आदि अनुसूचित जातियों/जनजातियों की नौकरी के सम्बन्ध में स्थिति का पुनरीक्षण करने के लिए आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडू तथा पश्चिम बंगाल में सीधे संबधित मुख्य मंत्रियों के अधीन विशेष एकक/समितियां स्थापित की गई हैं । उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जतियों के सदस्यों पर किए गए अपराधों के मामलों की शिकायतों की शीघ्र जांच करने तथा कानून के अनुसार कार्यवाही करने के लिए

पुलिस उपमहानिरीक्षक के चार्ज मे एक विशेष एकक स्थापित किया गया है। गुजरात में, हरिजनो तथा अन्य अल्पसंख्यकों पर अत्याचारो की गम्भीर शिकायतो की जाच करने के लिए राजकोट और बडौदा मे पुलिस अधिकारियों के चार्ज मे विशेष एकक स्थापित किये गये है। इस के अतिरिक्त पुलिस सहायक महानिरीक्षक के स्तर के एक अधिकारी द्वारा राज्य के पुलिस महानिरीक्षक के कार्यालय मे इस समस्या पर विशेष रूप से कार्यवाही की जाती है।

अस्पृश्यता (अपराध) संशोधन तथा प्रकीर्ण उपबन्ध विधेयक संसद् मे प्रस्तुत किया जा चुका है। विधेयक मे अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 के उपबन्धो के बेहतर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने तथा अस्पृश्यता अपराधो के लिए अधिक बडा दण्ड देने की व्यवस्था है।

Growth Centres in Backward Areas

2232. SHRI P. R. SHENOY: Will the Minister of INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to establish 'Growth Centres' in industrially backward areas during the Fifth Plan;

(b) if so, the names of Growth Centres already selected; and

(c) the principles on which these centres will be selected in future?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES (SHRI A. P. SHARMA): (a) Government have decided to select Growth Centres/Focal Points in backward areas for package development of small industries.

(b) A statement showing the Growth Centres/Focal Points so far identified is attached.

(c) Some of the important factors which are considered in selecting Growth Centres/Focal Points are infrastructural facilities like developed land, transport and communications, water, power and the availability of raw materials.

Statement

Sl. No.	Name of State	Name of backward district	Growth Centre Selected
1	2	3	4
1	Andhra Pradesh . .	Chittoor	Tirupathi
2	Bihar . . .	Bhagalpur Champaran Darbhanga	Cal-gong Raxaul Jayanagar
3	Gujarat . . .	Junagarh Surendranagar	Talala Block Surendranagar (full Distt.)
4	Goa	Mapusa Town	Mapusa Town
5	Himachal Pradesh . . .	Kangra	Damtal
6	Kerala	Alleppey	Shertallai